किसान की व्यथा किसान की जुबानी

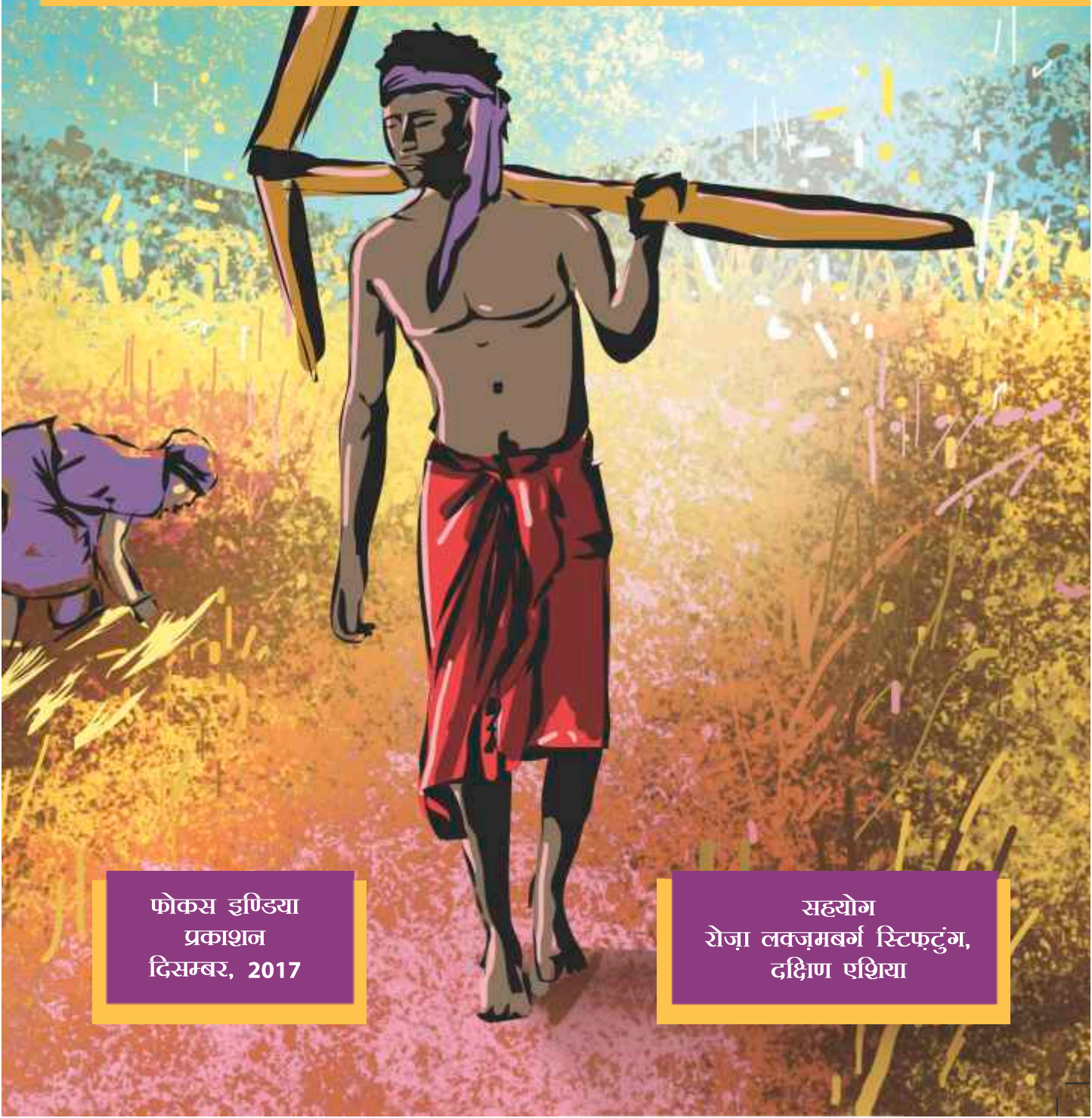

फोकस इण्डिया
प्रकाशन
दिसम्बर, 2017

सहयोग
रोज़ा लक्ज़मबर्ग स्टिफ़्टुंग,
दक्षिण एशिया

किसान की व्यथा किसान की जुबानी

FOCUS ON THE GLOBAL SOUTH

किसान की व्यथा कियसप कर जुबानी

चित्रकार : **अजीत लाकड़ा**

आलेखक : **हरिप्रकाश (उर्फ सोनू शर्मा)**

मार्ग दर्शन : **अफ़सर जाफ़री**

प्रकाशन : **दिसम्बर, 2017**

द्वारा प्रकाशित और इस पुस्तिका की प्रतियां पाने के लिए संपर्क : **फोकस ऑन द ग्लोबल साउथ**
33–डी, तीसरी मंजिल, विजय मंडल एनक्लेव
डी.डी.ए. एस.एफ.एस. फ्लैट्स, कालू सराय, हौज खास
नई दिल्ली–110016
टेलीफोन : 91–11–26563588 , 41049021
http://focusweb.org/

सहयोग : **रोज़ा लक्जमबर्ग स्टिफटुंग, साउथ एशिया**
सेंटर फोर इंटरनेशनल कॉ–ऑपरेशन
सी–15, दूसरी मंजिल, सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया मार्केट,
नई दिल्ली–110016
www.rosalux-southasia.org
"Sponsored by the Rosa Luxemburg Foundation e.V. with funds of the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of the Federal Republic of Germany."
"Gefördert durch die Rosa-Luxemburg-Stiftung e.V. aus Mitteln des Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland"

फोटो साभार : अजीत लाकड़ा

डिजाइन एवं मुद्रण : **पुलशॉप**, 9810213737

इस पुस्तिका की विषयवस्तु का इस शर्त के साथ बिना–रोक टोक के पुनर्मुद्रण और उद्धृत किया जा सकता है कि इस स्रोत का उल्लेख किया जाए। फोकस ऑन द ग्लोबल साउथ उस प्रकाशित सामग्री को पाने पर आभारी रहेगा, जिसमें इस रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है।

यह एक अभियान प्रकाशन है और निजी वितररण के लिए है!

परिचय

भारत देश में प्राचीन काल की एक कहावत है। "उत्तम खेती मध्यम बान करत चाकरी कुकर निदान"

इसका अर्थ है कि भारत में खेती करना सबसे उत्तम काम माना जाता था, व्यापार का दूसरा स्थान था, अंत में नौकरी करना। आज परिस्थितियां बदल गई है, नौकरी करना आज सर्वोत्तम काम माना जा रहा है। इस काम के लिए तो प्रत्येक क्षेत्र में बड़ा कंपटीशन चल रहा है, आज किसान अपनी खेती की जमीन बेचकर अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर नौकरी ही कराना चाहता है, चाहें वो नौकरी सरकार की हो या निजी कंपनी की । गांव से किसान पलायन कर के शहरों में रोजगार के लिए जा रहे हैं और वहां जाकर रिक्शा चलाने का काम, फल सब्जी बेचने का काम, कचरा उठाने का काम, बड़े-बड़े घरों में नौकर, माली, सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर का काम करने पर मजबूर है और यह सब नहीं मिलने पर वह सड़क पर भीख मांगता है। यह रोजगार भी पक्के नहीं है, पता नहीं आज है तो कल नहीं। गांव से विस्थापित किसान शहरी आबादी के लिए सिर्फ सस्ता मजदूर बनकर रह गया है। इस व्यवस्था के चलते गांव का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है और शहरों में जनसंख्या घनत्व बढ़ता जा रहा है। यह तथाकथित विकास का राक्षस ग्रामीण सभ्यता को डसता जा रहा है।

हम भारत में खेती के इतिहास पर नजर डालें तो हमें भारत मे कृषि प्रधान व्यवस्था देखने को मिलती है। शायद इसी व्यवस्था के चलते भारत को कृषि प्रधान देश कहा गया। इसी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के चलते भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। भारत का किसान पूरी तरह से आत्मनिर्भर था, जिसका कारण जीरो बजट खेती करना था, जिसमें लागत नहीं के बराबर थी। मगर हमारा किसान इतना उन्नत और कुशल था की उसने भारत को विभिन्न फसलों की अनगिनत प्रजातियां दी। लेकिन आज परिस्थिति बदल गयी है, भारत का किसान कर्ज के चलते या तो खेती बेंच रहा है या आत्महत्या करने को मजबूर है। पिछले 20 वर्षों मे 3.5 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके है और प्रतिदिन लगभग 2400 किसान खेती छोडकर शहरो मे सस्ते मजदूर बन रहे है। इन सब कारणो को जाने विना खेती और किसान को बचाना संभव नही है।

हमारी परंपरागत खेती हमारे परंपरागत ज्ञान और शारीरिक श्रम पर आधारित थी और पीढ़ी-दर-पीढ़ी यह ज्ञान हमें विरासत में मिलता चला आ रहा था। जब तक कोई भी व्यवस्था स्वदेशी होती है तब तक उस में बाहरी व्यवस्थाओं का हस्तक्षेप नहीं होता है। भारत का किसान परंपरागत खेती और जीरो बजट खेती करता था, जिसके कारण किसान खुशहाल और कर्जमुक्त था।

1. किसान ट्रैक्टरों की जगह बैल एवं हल से खेती करता था जिससे उसका डीजल पेट्रोल का खर्च बच जाता था।
2. भारत की खेती में जैविक परंपरागत बीजों का प्रयोग होता था जो ग्रामीण महिला संरक्षित करके रखती थी।
3. खेती में गाय/ पशुओं के गोबर का प्रयोग किया जाता था जिससे खेती में मित्र कीटों की बढ़ोतरी होती थी जो कि किसान और प्रकृति के संतुलन में सबसे बड़े सहायक होते थे। इससे जमीन की उर्वकर्ता और नमी बनी रहती है।

4. पशुओं का मूत्र और नीम की पत्तियों का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता था। जिसका मनुष्य के स्वास्थ पर कोई प्रभाव नहीं था।
5. खेती का एक हिस्सा अन्न (मनुष्य/पक्षियों) के खाने के लिए दूसरा हिस्सा तना (पशुओं/जानवरों) चारे के लिए और तीसरा अंतिम हिस्सा जड़ (मिट्टी) के उपजाऊपन के लिए होता था।

हमारी प्राचीन खेती हमारे जीवन यापन के लिए होती थी और ये पूर्णतः जीरो बजट होती थी, जिसके कारण किसान कर्जमुक्त और खुशहाल था।

दूसरी तरफ आधुनिक खेती है जिसे व्यवसाय खेती या पूंजीवादी खेती कहना ही ठीक रहेगा। इस व्यवस्था ने किसान के परंपरागत ज्ञान और शारीरिक श्रम को खत्म करके किसानों को कर्जदार बना बना दिया है या बड़े किसान या पूंजीपतियों का मजदूर बना दिया है। आधुनिक खेती में स्वदेशी व्यवस्था/ परंपरागत व्यवस्था खत्म हो गई और विदेशी व्यवस्था जिसमें आधुनिक और अति महगे बीज, रासायनिक खाद, बड़ी बड़ी मशीनों जैसे उपकरण इस्तेमाल हो रहे हैं जिससे खेती में बचत से ज्यादा खर्चा हो रहा है।

1. किसान खेती में ट्रैक्टरों और मशीन का प्रयोग कर रहा है जिससे उसकी आमदनी का मोटा हिस्सा पेट्रोल, डीजल, किराए के ट्रैक्टर और खुद के ट्रैक्टर खरीदने में जा रहा है।
2. किसान के पास खुद का बीज नहीं है क्योंकि व्यवसायी खेती ने किसान के खुद का बीज खत्म कर दिया है और विदेशी कंपनियों ने जैव यांत्रिकी तकनीकों से जहरीले बीज बना दिए हैं जिसके बीजो के साथ-साथ किसानों का चिकित्सा खर्च भी बहुत बढा हैं। बीटी कॉटन जैसे जी.एम बीज जो जहरीले होने के साथ-साथ इनको खेती में दोबारा उगाया नहीं जा सकता हैं लेकिन ये किसान को महंगे दामों पर खरीदने पड़ रहे हैं।
3. यूरिया का प्रयोग खाद के रुप में करने से किसान के खर्चे बढे हैं और ऐसा भी माना जाता है कि जब से खेती में यूरिया आया तब से खेती में शत्रु कीटों की संख्या बढ़ी है क्योंकि यूरिया से मित्र-कीट मर जाते हैं और जमीन जो मित्र-कीटों के कारण पोली होती थी, वो आज सख्त और बंजर हो गई है ।
4. खेती में शत्रु कीटों के आतंक के चलते हमारे किसान का कीटनाशक का खर्च बहुत बढा है, जहरीले कीटनाशकों के चलते गांव की नदियां और जलाशयों का पानी और जमीनी जलस्तर भी जहरीला हो गया है। प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है, अब बे मौसम बारिश ,ओलावृष्टि और सूखा किसान को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

आधुनिक खेती के चलते हमने मनुष्य जीवन, पशु और पक्षियों को, यहां तक कि अपनी धरती मां को भी बीमार बना दिया है। इस खेती से किसान को नहीं बल्कि पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा मिला है । आधुनिक खेती और इससे बढ़ते खर्च किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे हैं। हम यहाँ कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं जिससे यह दिखता है की आधुनिक खेती किसान को नहीं बल्कि पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है

जब सरकार ने पहली बार सन 1967 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद की तब गेहूं का भाव 76 रूपये/ क्विंटल था जो आज 1700 रुपए/क्विंटल है। देखने में तो गेहूं का भाव खूब बढ़ा हुआ दिखता है लेकिन इसी एक कुंटल गेंहू से पहले किसान जो सामान खरीदता था, उसकी तुलना करें तो पता चलेगा कि किसान आत्महत्या करने पर क्यों मजबूर है और उसकी खेती का घाटा कितना है।

1. सन 1967 में गेहूं का भाव 76 ₹ क्विंटल था और सोना 190 रूपये तोला था।, तब 2 क्विंटल गेहूं बेचकर किसान एक तोला सोना खरीद सकता था लेकिन आज एक तोला सोना खरीदने के लिए किसान को लगभग 18 क्विंटल गेहूं बेचने पड़ेंगे।
2. डीजल 38 पैसा लीटर था, तब किसान एक क्विंटल गेहूं बेंचकर 200 लीटर डीजल खरीदा जा सकता था लेकिन आज एक क्विंटल गेंहू बेंचने पर सिर्फ 30 लीटर डीजल खरीद पाता है।
3. ईट का भाव 25 पैसे/10 ईट था, इसका मतलब किसान एक क्विंटल गेहूं बेच कर 3000 ईट खरीद सकता था जो कि आज एक क्विंटल गेहूं बेचकर सिर्फ 350 ही खरीद सकता है।
4. सीमेंट का भाव 5 रूपये बोरी था, तब किसान एक क्विंटल गेहूं बेचकर 15 बोरी सीमेंट खरीद सकता था लेकिन आज एक क्विंटल गेहूं बेचकर सिर्फ 5 बोरी सीमेंट खरीद सकता है।
5. सन् 1967 में सरकारी अध्यापक की तनख्वाह 70 रूपये मासिक थी, अगर उस समय सरकारी अध्यापक को एक क्विंटल गेहूं खरीदना पडे, तो उसको 6 रूपये अपने घर से देने होते थे लेकिन आज सरकारी अध्यापक एक माह के वेतन से लगभग 30 क्विंटल से ज्यादा गेहूं प्रतिमाह खरीद सकता है।

अब सवाल उठता है कि जब गेहूं का भाव 76 रूपये क्विंटल था तब किसान फायदे में था लेकिन अब गेहूं का भाव 1700 रूपये क्विंटल है तब देश का किसान कर्जदार है और आत्महत्या कर रहा है।

इस किताब के माध्यम से हमने कोशिश की है कि देश के किसान की वास्तविक स्थिति को उस जनता के सामने लाया जाए, जो किसान का अन्न खाकर जिंदा है। इस किताब का उद्देश्य भारत की साधारण जनता को किसान की मन की बात सुनान है। इस पुस्तिका मे किसान की समस्याओं और समाधान की दिशा मे काम करने की कोशिश की गयी है, बस एक ग्रामीण किसान परिवार की स्थिति को हमने समझने की कोशिश की है और उन्ही के परंपरागत ज्ञान से समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश भी गयी है।

हमने ये भी दर्शया है की आखिर हमारे देश का किसान आंदोलनों के माध्यम से देश और राज्य की सरकारों से क्या कहना और क्या करवाना चाहता है? हमने यह भी कोशिश की है कि इस किताब के माध्यम से यह सभी आंदोलन की बात जनता तक पहुंचे। आखिर किसान कब तक चुप बैठेगा और अन्नदाता की पुकार कब तक अनसुनी कर दी जाएगी।

तमिलनाडु के किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर अपने मन की बात प्रधानमंत्री जी को सुनाने आए लेकिन जब प्रधानमंत्री ना मिले तो वो नाराज होकर भरी गर्मी में प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने नग्न प्रदर्शन करने लगे, उनका आंदोलन रोज नए मोड़ लेता गया, कभी मरे हुए चूहे खाकर प्रदर्शन करना पड़ा, कभी अर्ध मुंडन कराना पड़ा तो कभी अपना ही मूत्र पीना पड़ा । उसके बाद मध्य प्रदेश और

महाराष्ट्र के किसान को फसलों का उचित भाव ना मिला तो उन्हे सड़कों पर आना पड़ा। फसल, सब्जी और दूध सभी सड़कों पर फेंके गए। मध्य प्रदेश में किसानों पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई जिसमें पांच गरीब किसान शहीद हो गये। मध्यप्रदेश में किसान अपनी जमीन को बचाने के लिए "जल सत्याग्रह" करते देखे गये तो ऐसा ही राजस्थान के नीदड में किसान अपनी जमीन को बचाने के लिए, जमीन में गड्ढा खोदकर "जमीन सत्याग्रह" करते देखे गये।

पिछले सत्तर सालों में विकास के नाम पर किसानों की करोड़ों एकड़ जमीन, रेलवे मार्ग, सड़क मार्ग, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज,सरकारी भवनों, और सरकारी कार्यालयों के नाम पर ली गई। लेकिन अब हमारा किसान थोड़ा जागरुक होकर सड़कों पर आ रहा है। हमारा किसान कभी प्राकृतिक आपदाएं तो कभी सरकार की नीतियों का शिकार हो रहा है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर किसानों के बीच जाकर हमने इस किताब को लिखने की कोशिश की है।

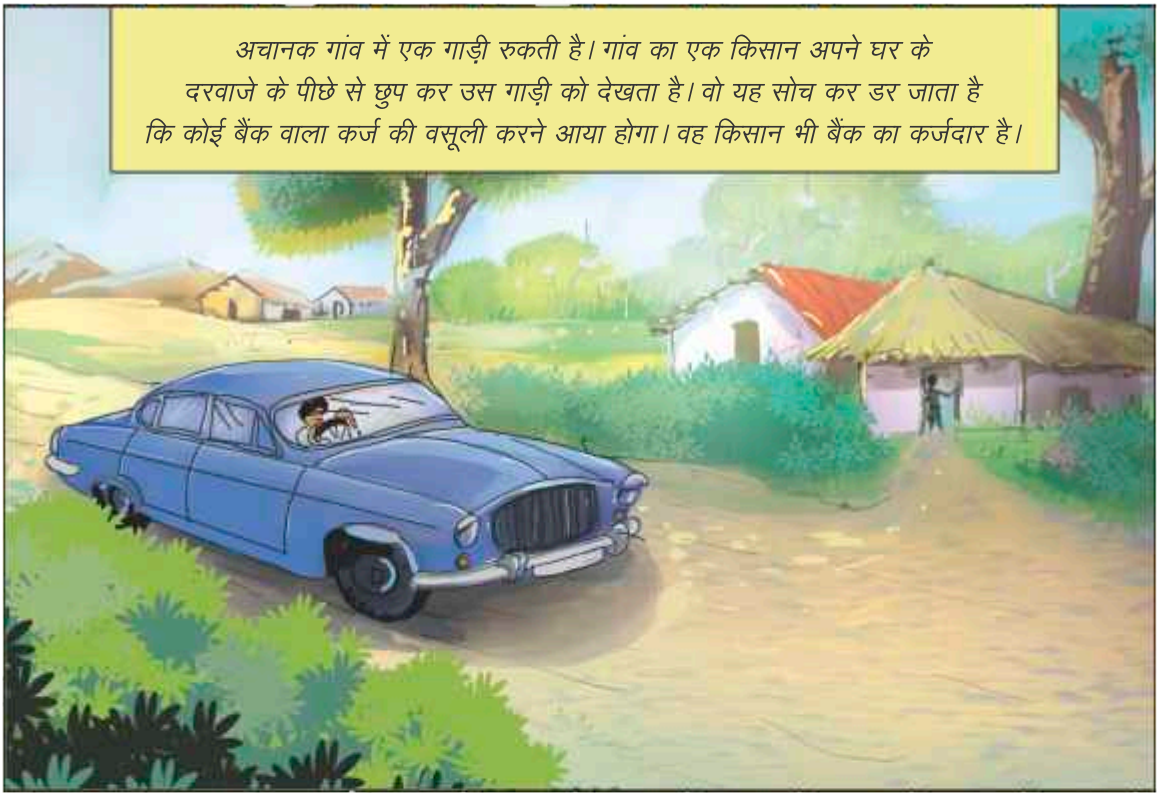
अचानक गांव में एक गाड़ी रुकती है। गांव का एक किसान अपने घर के
दरवाजे के पीछे से छुप कर उस गाड़ी को देखता है। वो यह सोच कर डर जाता है
कि कोई बैंक वाला कर्ज की वसूली करने आया होगा। वह किसान भी बैंक का कर्जदार है।

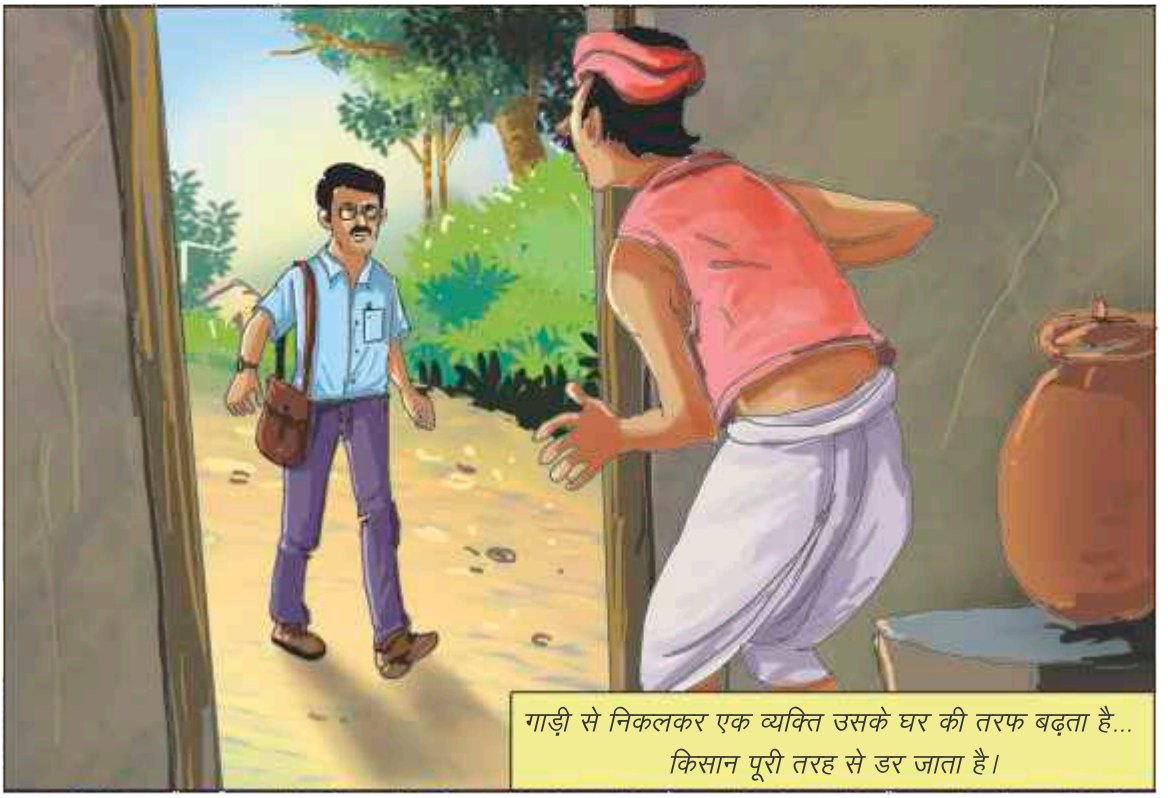
गाड़ी से निकलकर एक व्यक्ति उसके घर की तरफ बढ़ता है...
किसान पूरी तरह से डर जाता है।

डरिये मत !
मैं भी आपके ही जैसा एक आम इंसान हूं।
आप कौन हैं ??

मैं भी आपकी ही तरह एक किसान का बेटा हूं।
शहर में रहकर थोड़ा पढ़–लिख गया हूं।
अरे ! आपको देखकर
नहीं लगता कि आप एक किसान हैं।

क्या... ? मैं किसान नहीं हो सकता ?
माफ़ कीजिए पर आपको देखकर
मुझे लगा कि आप या तो किसी बैंक से हैं
या किसी खाद–बीज बेचने वाली कंपनी से।

अरे, मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
बाहर आओ, मैं तुमसे बात करने आया हूं।
तुम्हारी और दूसरे किसानों की स्थिति को समझना चाहता हूं।
किसान कुछ सोच कर बाहर आता है।

किसान की हालत देखकर
वह व्यक्ति दुखी हो जाता है। न तो
उसके तन पर ठीक से कपड़े होते हैं,
न ही उसके पैरों में चप्पल।
किसान हाथ जोड़कर
खड़ा हो जाता है
और पास में रखी चारपाई
पर बैठने के लिए बोलता है।

लेकिन वह किसान के साथ नीचे चटाई पर बैठ जाता है
जिससे किसान को अपनापन महसूस होता है। किसान का डर धीरे–धीरे खतम हो जाता है।
लेकिन मुझे देखकर
तुम डर क्यों गए थे?
मैंने बैंक और बीज कंपनी से उधार ले रखा है।
मुझे लगा आप मुझसे कर्ज वसूलने आये हैं।
इसलिए मैं डर गया था।

लेकिन बैंक तो किसान के फायदे के लिए होते हैं और खाद–बीज की कंपनियां भी तो किसान को फायदा पहुंचाने के लिए होती हैं – मैंने तो ऐसा ही सुना है।
लगता है शहर के पढ़े–लिखे लोगों को हमारी स्थिति के बारे में कोई अंदाजा नहीं है, तभी ये ऐसा कह रहे हैं।

खेती में लागत बहुत बढ़ गई है। उत्पाद का सही दाम भी नहीं मिलता। हमारी तो लागत भी नहीं निकल पाती। फसल का नुकसान अलग।
ये तो बड़ी चिंताजनक स्थिति है, फिर आपका गुजारा कैसे हो रहा है ?

साहब, क्या बताएं... खेती में लागत इतनी बढ़ गई है
कि किसान को लाखों का कर्ज लेना पड़ रहा है। ये घर भी गिरवी पर है।
आए दिन बैंक वाले धमकाने आ जाते हैं।
आपको देखकर लगा कि आज तो यह घर भी हाथ से गया।
ओह माय गॉड !!!

पूरे देश का पेट भरने वाला... हमारा 'अन्नदाता'... इस तरह कर्ज में डूबा हुआ है...
हम शहर के लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम।
आप अकेले इतने कर्जदार हैं
या आप जैसे और भी किसान हैं ?
सारा गांव कर्जदार है।
आप चाहें तो खुद चल कर देख सकते हैं।

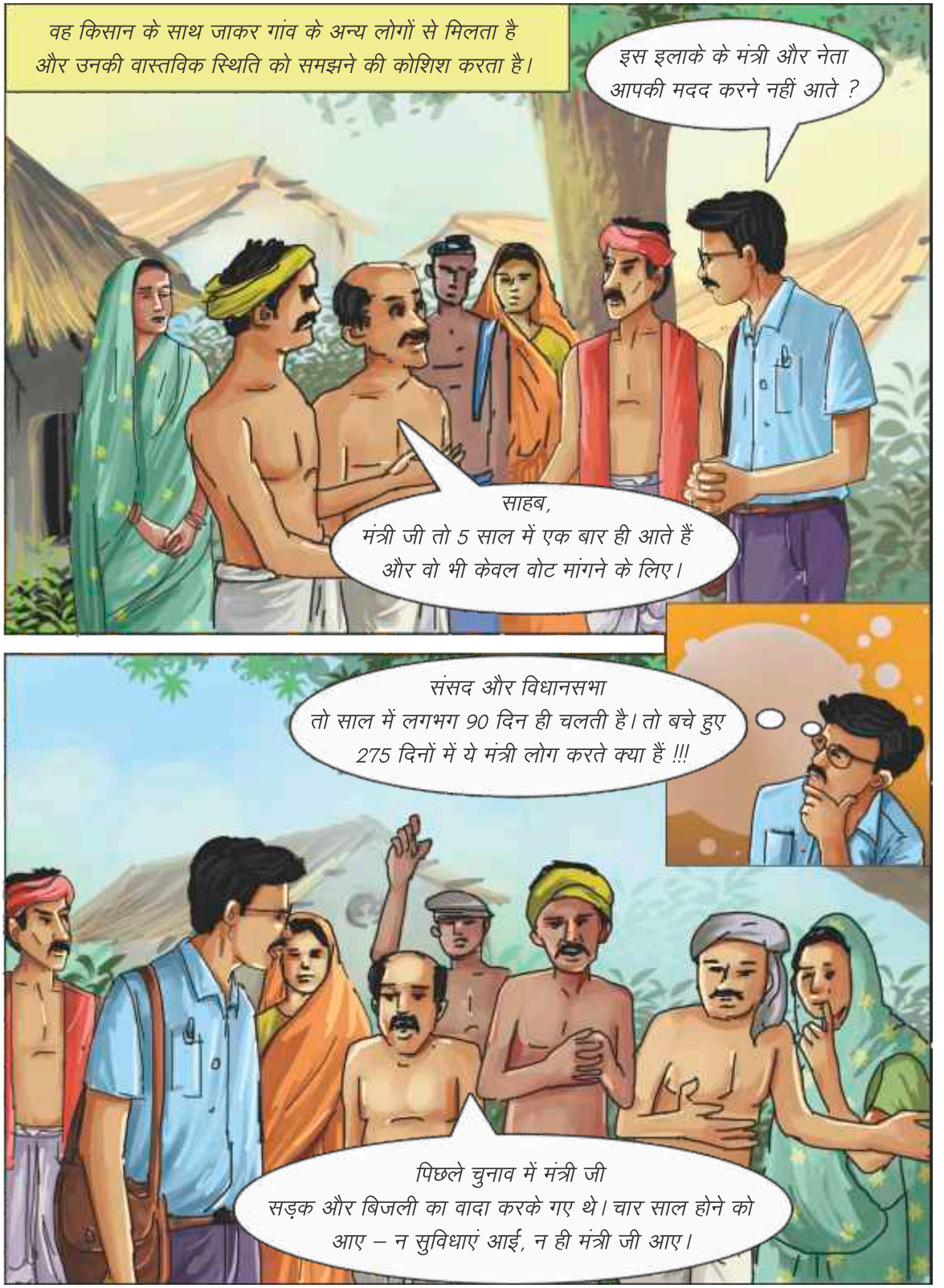
वह किसान के साथ जाकर गांव के अन्य लोगों से मिलता है और उनकी वास्तविक स्थिति को समझने की कोशिश करता है।
इस इलाके के मंत्री और नेता आपकी मदद करने नहीं आते ?
साहब, मंत्री जी तो 5 साल में एक बार ही आते हैं और वो भी केवल वोट मांगने के लिए।
संसद और विधानसभा तो साल में लगभग 90 दिन ही चलती है। तो बचे हुए 275 दिनों में ये मंत्री लोग करते क्या हैं !!!
पिछले चुनाव में मंत्री जी सड़क और बिजली का वादा करके गए थे। चार साल होने को आए – न सुविधाएं आईं, न ही मंत्री जी आए।

वह व्यक्ति वापस अपने शहर की तरफ लौटता है।
भारत एक कृषि प्रधान देश है पर विकास की इस अंधाधुन्द दौड़ में हमने अपने किसानों और गांवों को बहुत पीछे छोड़ दिया है।

इस स्थिति के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा।

वह गांव से लौटकर सीधे मंत्री जी के पास जाता है।
नमस्कार मंत्री जी
जी नमस्कार

क्या आपको पता है कि आपके क्षेत्र के किसानों की वास्तविक स्थिति क्या है ?
जी पता है। तभी तो हम इतने प्रयास कर रहे हैं।
कैसा प्रयास
हम किसानों की आमदनी दोगुना कर रहे हैं
पर खेती में किसानों के खर्च लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर आमदनी बढ़ा भी दी जाए, तो इसका फ़ायदा किसान को नहीं बल्कि कृषि सामग्री बेचने वाली कंपनियों को अधिक होगा।
हम किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनका माल खरीदते हैं।

पर एम.एस.पी तो केवल 22 फसलों पर ही लागू है... और सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 6 प्रतिशत से ज्यादा किसानों को एम.एस.पी का कोई फायदा नहीं मिलता।
किसानों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हम उनको बैंक खाता दे रहे हैं... रसोई गैस सिलेंडर दे रहे हैं... शौचालय दे रहे हैं... और तो और डीजिटल इंडिया से मोबाइल और डाटा कनेक्शन दे रहे हैं...

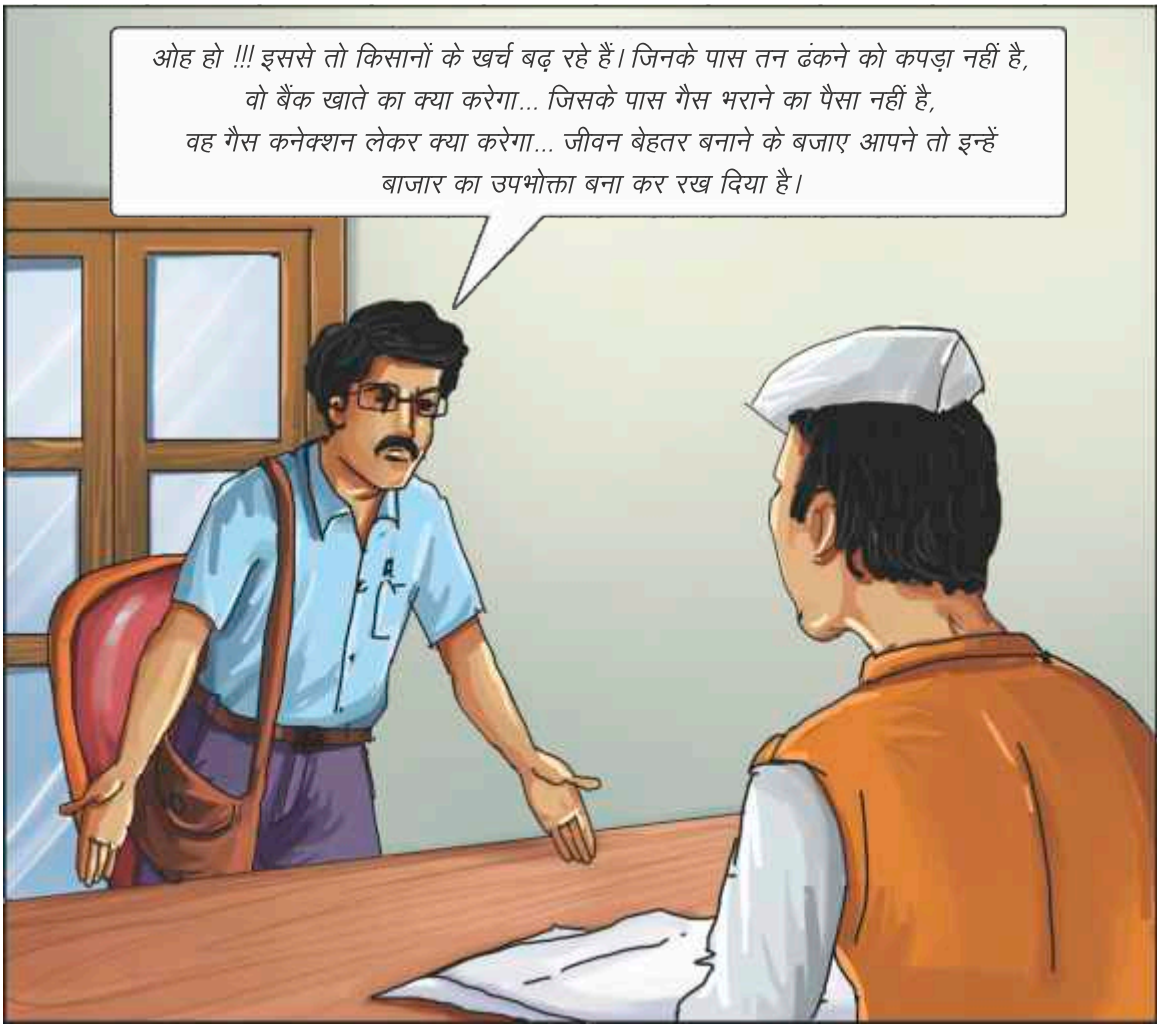
ओह हो !!! इससे तो किसानों के खर्च बढ़ रहे हैं। जिनके पास तन ढंकने को कपड़ा नहीं है, वो बैंक खाते का क्या करेगा... जिसके पास गैस भराने का पैसा नहीं है, वह गैस कनेक्शन लेकर क्या करेगा... जीवन बेहतर बनाने के बजाए आपने तो इन्हें बाजार का उपभोक्ता बना कर रख दिया है।

किसानों को तो मौसम की भी मार झेलनी पड़ती है। बेमौसम बरसात, सूखा, बाढ़, ओला वृष्टि से फसल अकसर बर्बाद हो जाती है।
हां, सही कहा आपने... इसीलिए तो हम फसल बीमा योजना लेकर आए हैं !

लेकिन मंत्री जी, फसल बीमा का फायदा किसानों को मिल कहां रहा है। बीमा कंपनी अगर 100 रुपये प्रीमियम ले रही है तो केवल 6 रुपये ही किसानों को भुगतान कर रही है। किसानों को मुआवज़ा देने के नाम पर बीमा कंपनियां अपनी जेब भर रही हैं।
हम हाइब्रिड बीज ला रहे हैं.. इससे उत्पादन भी बढ़ेगा और मुनाफ़ा भी...

पर उत्पादन तो पिछले 30 सालों में खूब बढ़ा है... तो फिर आप ही बताइये कि पिछले 15 सालों में 3 लाख किसानों ने आत्महत्या क्यों की ?
मंत्री जी चुप हो जाते हैं

दरअसल, खेती में उत्पादन बढ़ने से किसान को नहीं बल्कि पूंजीपति वर्ग को फायदा हुआ है।
ये लीजिए, मैं आपके लिए कुछ आंकड़े लाया हूं जिससे ये साफ हो जाएगा कि आज की बाजार व्यवस्था किसानों के लूट पर टिकी है। वर्ष 1967 में गेंहू का भाव 76 रु. क्विंटल था जबकि सोने का भाव 190 रु. तोला था। उस समय 2.5 क्विंटल गेंहू में एक तोला सोना खरीद सकते थे पर आज एक तोला सोना खरीदने के लिए 20 क्विंटल गेंहू भी कम पड़ेगा।

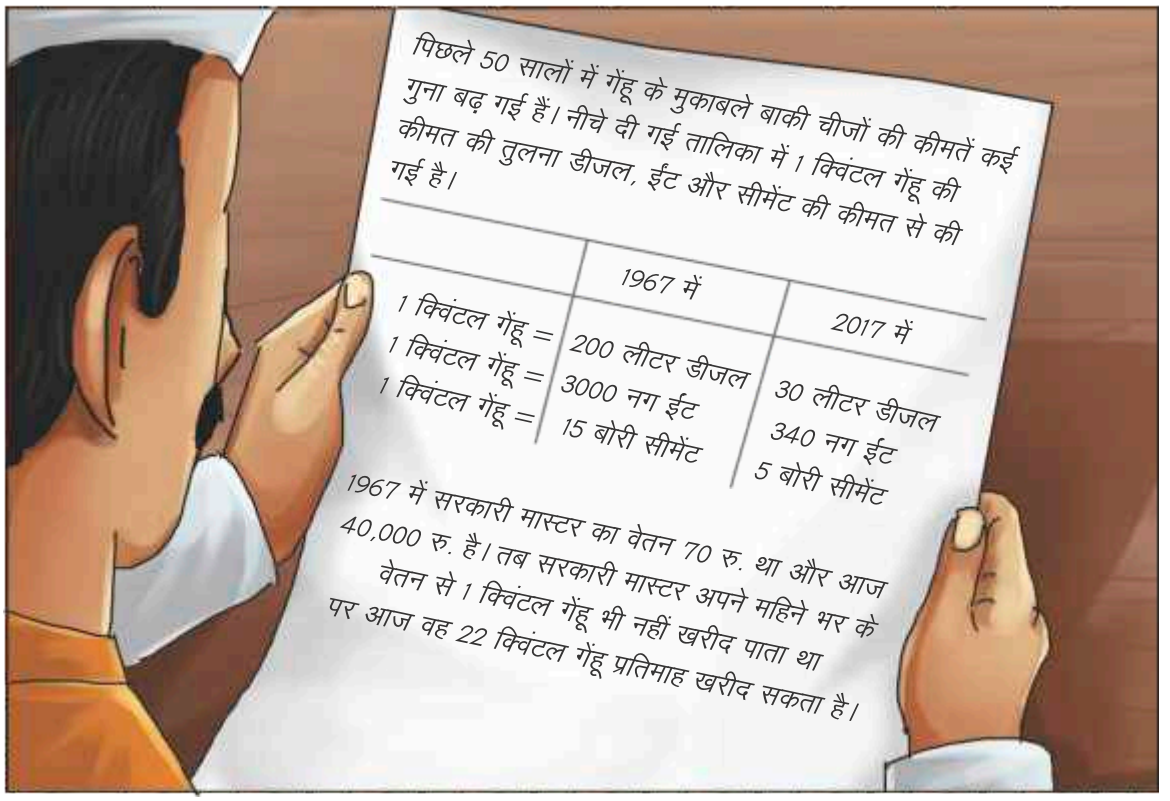
पिछले 50 सालों में गेंहू के मुकाबले बाकी चीजों की कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं। नीचे दी गई तालिका में 1 क्विंटल गेंहू की कीमत की तुलना डीजल, ईंट और सीमेंट की कीमत से की गई है।
1967 में
2017 में
1 क्विंटल गेंहू = 200 लीटर डीजल
30 लीटर डीजल
1 क्विंटल गेंहू = 3000 नग ईंट
340 नग ईंट
1 क्विंटल गेंहू = 15 बोरी सीमेंट
5 बोरी सीमेंट
1967 में सरकारी मास्टर का वेतन 70 रु. था और आज 40,000 रु. है। तब सरकारी मास्टर अपने महिने भर के वेतन से 1 क्विंटल गेंहू भी नहीं खरीद पाता था पर आज वह 22 क्विंटल गेंहू प्रतिमाह खरीद सकता है।

हम्म... हमने किसान समृद्धि आयोग बनाया है...
जल्द ही वह आयोग हमें सुझाव देगा। इसमें किसान और किसान संगठन दोनों को हमने शामिल किया है।

क्या स्वामीनाथन आयोग से भी बड़ा कोई आयोग बन सकता है ?
पहले उसे तो लागू करें। रही बात सुझाव की तो वह
किसान और किसान संगठनों द्वारा आपको मिलते रहेंगे।
अच्छा चलता हूं, नमस्कार !

मंत्री जी से मिलने के बाद वह व्यक्ति किसान संगठनों से मिलने जाता है।
नमस्कार
जी नमस्कार
जी नमस्कार
आप किसानों और खेती की समस्याओं से निपटने के लिए कैसे संघर्ष करते हैं ?
आंदोलनों के माध्यम से
क्या आंदोलनों से किसानों को कोई फायदा पहुंचा है ?
प्रयास जारी है पर परिणाम संतोषजनक नहीं है।

देखिये, आंदोलन के माध्यम से सिर्फ़ विरोध दर्ज होता है... हमें व्यवस्था परिवर्तन के लिए जागरूकता अभियान चलाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें।
हां... ये सही कहा आपने। हम आपके साथ हैं।

अच्छा... मंत्री जी ने बताया कि आपमें से कुछ लोग 'किसान समृद्धि आयोग' के भी सदस्य हैं। इस बारे में आप लोग क्या कर रहे हैं।
अभी तक हम ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाते थे... परंतु अब हम आयोग के सदस्य होने के नाते अपने सुझाव सीधे सरकार के सामने रखेंगें। उम्मीद है सरकार हमारे सुझावों पर कुछ संज्ञान लेगी।
जी धन्यवाद !

वह व्यक्ति शहर के अन्य जागरूक व्यक्तियों के साथ किसानों की समस्या के ऊपर एक बैठक करता है।
आपको अपने देश के 6 लाख गांवो में रह रहे किसानों की स्थिति के बारे में पता है ?
यार सुना तो है कि स्थिति बहुत खराब है... आए दिन किसानों के आंदोलन और प्रदर्शन हो रहे हैं।
मैंने दिल्ली में किसानों को अपना मूत्र पीकर, तथा घास और चूहा खाते, प्रदर्शन करते हुए देखा था।
कई किसान प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग में गोली खाकर मर गए थे – ऐसा मैंने एक बार समाचार मे देखा था।

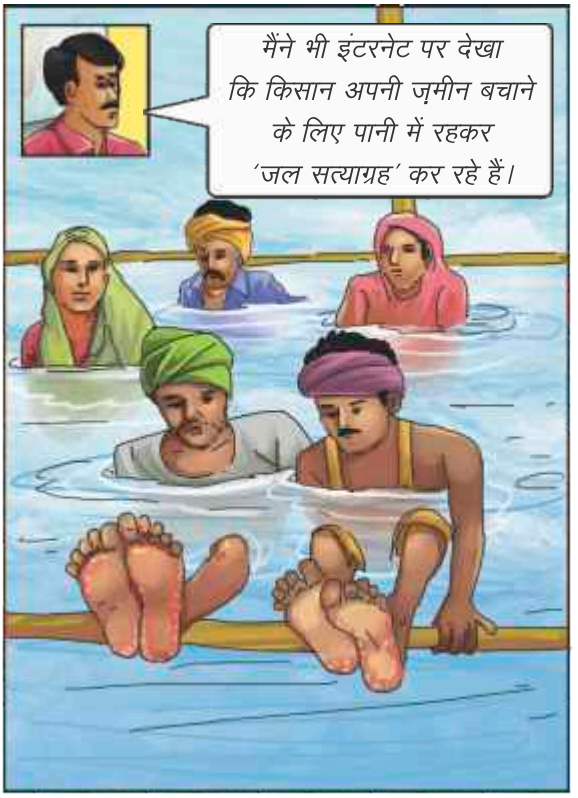
मैंने भी इंटरनेट पर देखा
कि किसान अपनी ज़मीन बचाने
के लिए पानी में रहकर
'जल सत्याग्रह' कर रहे हैं।

हां मैने भी टी.वी. में एक
दिन देखा कि राजस्थान के किसान
अपनी जमीन बचाने के लिए
जमीन सत्याग्रह कर रहे थे।

अरे मैंने तो अपनी आंखों से महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश
के किसानों को सड़क पर टमाटर,
आलू, प्याज और दूध को फेंकते हुए देखा था !

तो इससे एक बात साफ हो जाती है
कि अपने जागरूकता अभियान
में हमें मीडिया का भी सहयोग लेना चाहिए।
हम सबको मिलकर कुछ करना चाहिए।
हम क्या करेंगे...
क्या हम आंदोलन करेंगे ?

हम जागरूकता अभियान चलाएंगे...
क्योंकि आंदोलन तो किसान संगठन भी कर रहे हैं
पर उसका परिणाम संतोषजनक नहीं हैं।
हां... हम मिलकर किसानों
के बीच जाएंगे और उन्हें जागरूक करेंगे।
हम लोगों से भी सीधा सम्पर्क करेगें और उन्हें
अन्नदाता का महत्व समझाऐगें और किसानों
से सीधा खरीदारी करने को कहेंगे।
ठीक है।

मैंने सूना है कि सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुना कर रही है।
मैं इस विषय मे मंत्री जी से मिला था। आय का तो नहीं पता पर खर्च ज़रूर दुगना हो जाएगा।

वह कैसे?
हाइब्रिड बीज, रासायनिक दवाइयां, फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड और भावंतर योजना – इन सभी से तो किसानों के खर्च ही बढ़ेंगे और क्या

अरे, जब खर्च ही बढ़ेंगे तो आय दोगुना कैसे होगी ?
शायद हमारी सरकार किसानों को ग्राहक और उपभोक्ता बनाना चाहती है... जिससे पूंजीवाद को बढ़ावा मिले और देश की जी.डी.पी. बढ़े।
इससे जी.डी.पी. कैसे बढ़ेगी?

जब किसान का खर्च बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो देश की जी.डी.पी. भी बढ़ेगी।
अब समझ में आया कि सरकार किसानों को 'ग्राहक' और 'उपभोक्ता' क्यों बना रही है।
ठीक है हम सभी इस अभियान में शामिल हैं।

सबसे पहले हमें किसानों के
खर्च कम करने के उपाय ढूंढ़ने होंगे?
वह कैसे?

सरकार बजट में हर साल किसानों को
10 लाख करोड़ का ऋण देती है जो किसानों तक
कभी नहीं पहुंचता। हम किसानों को जागरूक कर
के उसी ऋण से गांव–गांव में कुटीर उद्योग
लगाएंगे और किसानों की आय, खेती
के साथ–साथ अन्य स्त्रोतों से भी बढ़ाएंगे।
शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय – जो
आज व्यापार बन गयी हैं – सभी को सेवा बनाना होगा...
इस पर किसानों के काफी पैसे खर्च होते हैं।

चलो चलें गांव की ओर

सभी लोग गांव की ओर चल पड़ते हैं। उनका उद्देश्य यह जानना है कि किसानों के खर्च कहां–कहां हो रहे हैं और उन्हें कम करने के उपाय क्या हैं।

गांव के चौपाल में लोग किसान पंचायत के लिए इकट्ठे होते हैं।
सभी किसान इस बात से खुश हैं कि पहली बार कोई उनसे बात–चीत करने आया है
और उनकी समस्याओं को समझकर उनका हल निकालना चाहता है।

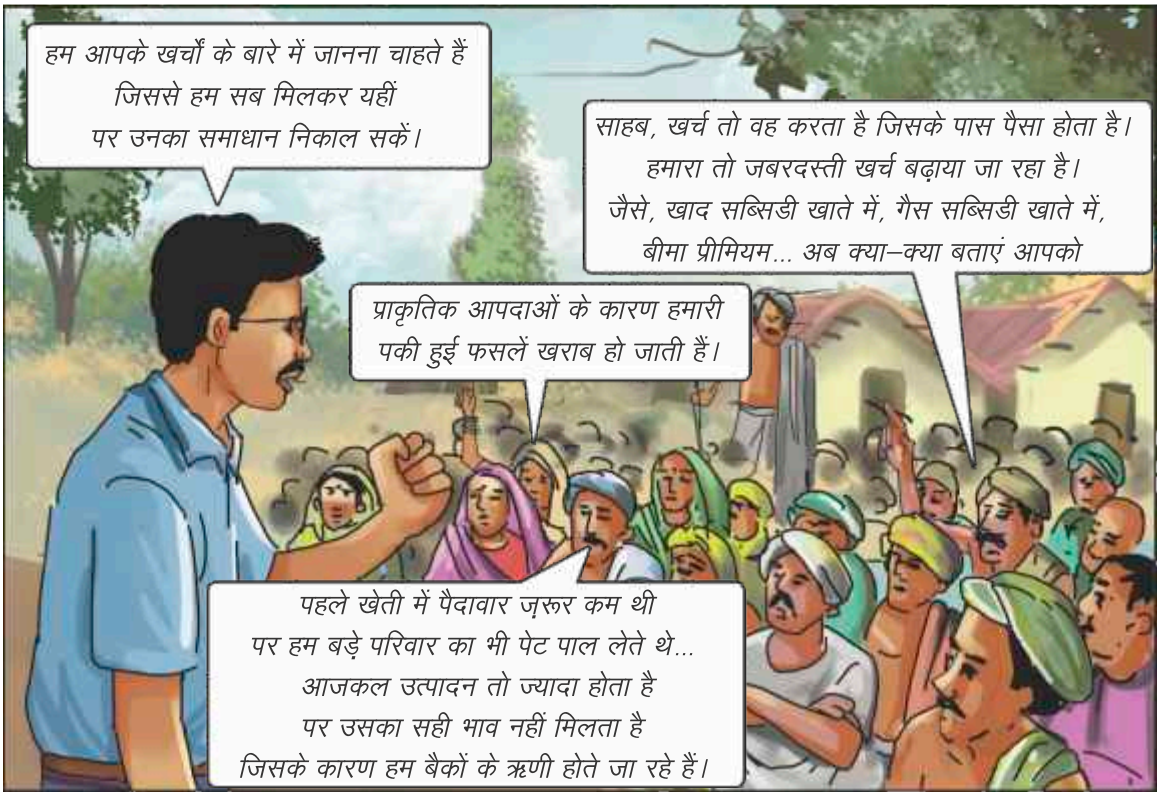
हम आपके खर्चों के बारे में जानना चाहते हैं
जिससे हम सब मिलकर यहीं
पर उनका समाधान निकाल सकें।
साहब, खर्च तो वह करता है जिसके पास पैसा होता है।
हमारा तो जबरदस्ती खर्च बढ़ाया जा रहा है।
जैसे, खाद सब्सिडी खाते में, गैस सब्सिडी खाते में,
बीमा प्रीमियम... अब क्या–क्या बताएं आपको
प्राकृतिक आपदाओं के कारण हमारी
पकी हुई फसलें खराब हो जाती हैं।
पहले खेती में पैदावार ज़रूर कम थी
पर हम बड़े परिवार का भी पेट पाल लेते थे...
आजकल उत्पादन तो ज्यादा होता है
पर उसका सही भाव नहीं मिलता है
जिसके कारण हम बैकों के ऋणी होते जा रहे हैं।

हमारा माल व्यापारी मानक देखकर सस्ता खरीदते हैं जबकि हम बिना मानक दिखाऐ महंगा सामान बाजार मे देते है।
साहब, जब हमारे पास खुद का बीज ही नहीं तो हम किसान कैसे हुए ? हमारा बीज तो विदेशी कंपनियों ने छीन लिया है।
जो बीज हमें 400–500 रु. किलो हाइब्रिड के नाम पर मिलता है, वही हमसे बाजार में 10–20 रु. किलो के भाव से खरीद लिया जाता है।
व्यापारियों के माध्यम से सरकार किसानों को लूट रही हैं।
खेती में अधिक यूरिया और कीटनाशक के इस्तेमाल से जमीन सख्त हो गई है। पानी ज्यादा लगता है और कीट भी ज्यादा आते हैं। इससे कीटनाशक की खपत और बढ़ गई है।

भूमि अधिग्रहण कानून के माध्यम से सरकार किसानों की जमीन छीन कर पूंजीपतियों को दे रही हैं।
हमारी जमीन है पर सरकार प्राकृतिक संसाधनों का हक हमें ही नहीं दे रही है।
चिकित्सा के अभाव मे हमारे बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। चिकित्सा आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है।
शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि हम बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते।
शिक्षा, चिकित्सा और न्याय आज सबसे बड़े व्यापार बन गए हैं... इसमें हमारा सबसे ज्यादा पैसा बर्बाद होता है।
बैंक आए दिन हमारे घरों की कुर्की कर रही है।
हमारे ऊपर इतना कर्ज है कि हमारे पास आत्महत्या करने के सिवाए और कोई चारा नहीं है।

किसान पंचायत में किसानों की व्यथाओं को सुनकर वे लोग बहुत दुखी हो जाते हैं और कुछ नया करने का संकल्प लेकर सीधे किसान संगठनों से दुबारा मिलते हैं।
हम लोग किसान पंचायत से आ रहे हैं। हमें लगता है कि हमें तुरन्त किसी मीडियाकर्मी से मिलना चाहिए।
नेक काम में देर कैसी! चलिये अभी चलते हैं।
जी कहिये..
नमस्कार! हम लोग कुछ आम नागरिक हैं और कुछ किसान संगठनों के प्रतिनिधि हैं। आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं।
जी नमस्कार जी

कैसे आना हुआ ?
हमारे देश में किसानों की हालत तो आपको पता ही है...
हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें।
बताइए... हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं?
हम किसानों को जागरूक करना चाहते हैं।
साथ ही हम आपके माध्यम से सारे देश को दिखाएंगे
कि पूरे देश का पेट भरने वाला किसान खुद भूखा है
और कैसे किसानों की लूट का खेल चल रहा है ?

वो तो ठीक है... परंतु... ???
परंतु क्या????

हमें इस काम के लिए बहुत सारे स्थानीय लोगों और स्थानीय पत्रकारों की आवश्यकता पड़ेगी....
बस इतनी से बात... इसकी चिंता आप न करें। हमारे संगठन के लोग आपकी पूरी मदद करेंगे। क्षेत्रीय स्तर पर हमारी अच्छी जान–पहचान है।

मीडियाकर्मी और किसान संगठनों के सहयोग से गांव–गांव में जागरूकता अभियान चलाया जाता है। गांव–गांव में जाकर किसान भाईयों और बहनों को संगठित किया जाता है।

हमारा सबसे ज्यादा खर्च रसायनिक खाद, बीज और कीटनाशकों पर होता है। जैविक खाद, पारम्परिक बीज और रसायन मुक्त खेती हमारा खर्च बचा सकते हैं। कुटीर उद्योग, पशु–पालन, मछली पालन, और छोटे प्रसंसकरण इकाईयां जैसे उद्यमों से हम अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं।
प्राकृतिक आपदा हो या सामुदायिक समस्या – हम सब एक साथ मिलकर सामना करेंगे। सदभाव और भाईचारा से हम अपने दुःख–दर्द दूर कर सकते हैं।
कोर्ट–कचहरी और पुलिस के मामलों को गांव के ही पंचायत में निपटाया जाए। इससे खर्च भी बचेगा और न्याय भी मिलेगा।
और सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी स्वायत्ता और संप्रभुता। अपनी सारी जरूरतों का सामान गांव में ही तैयार करके हम अपने आप को आत्म–निर्भर बना सकते हैं।

खुशहाल गांव और कर्जमुक्त किसान

गांव की अर्थव्यवस्था जिसमें गांव में ही कुटीर उद्योग, पशु पालन, मछली पालन, जैसे उद्यम हैं। गांव की जरूरत का सामान गांव में ही तैयार किया जाता है ताकि बाजार के महंगी चीजों में पैसे खर्च न हों। सदभाव, भाईचारा और भेदभाव रहित, एक आत्मनिर्भर गांव।

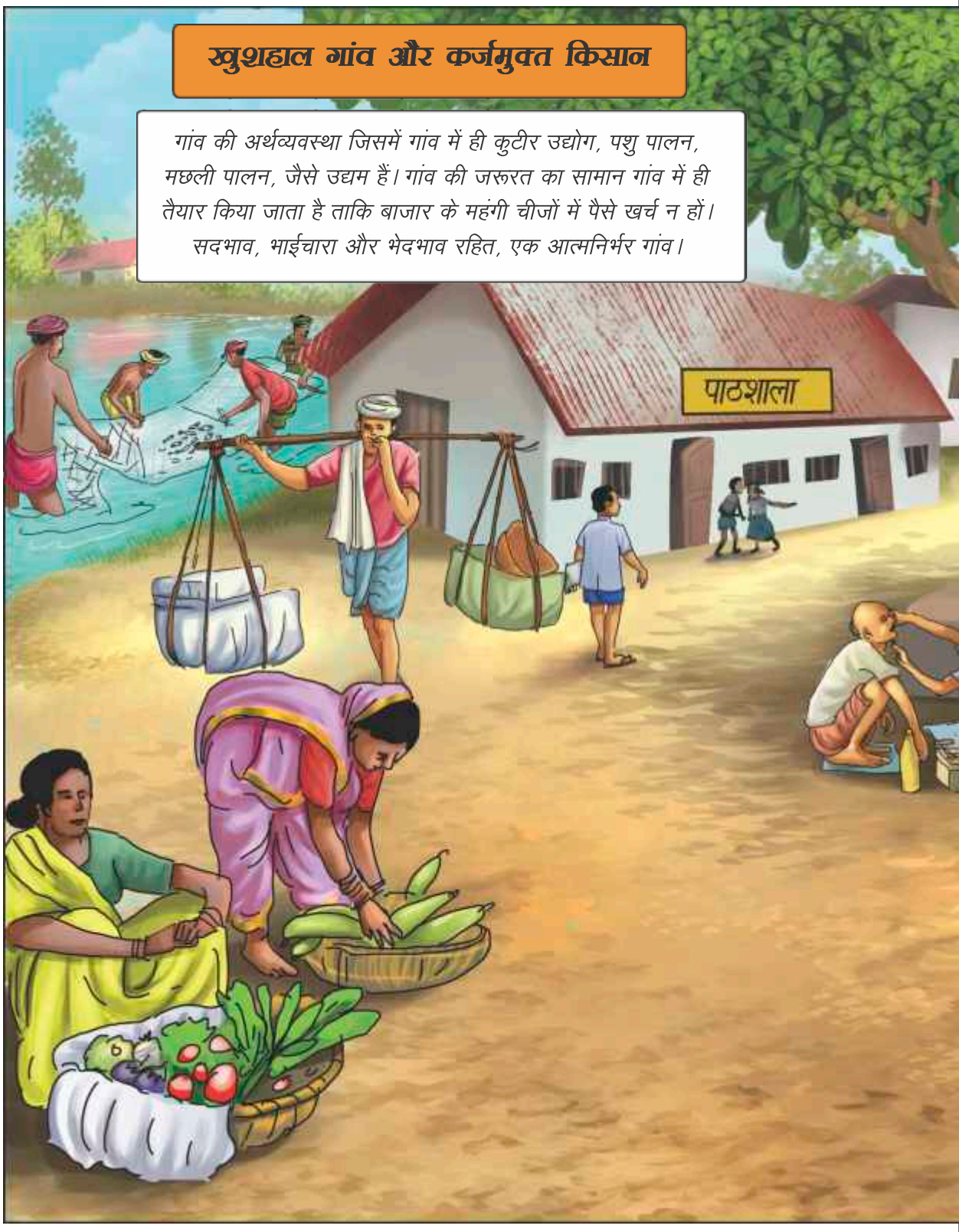

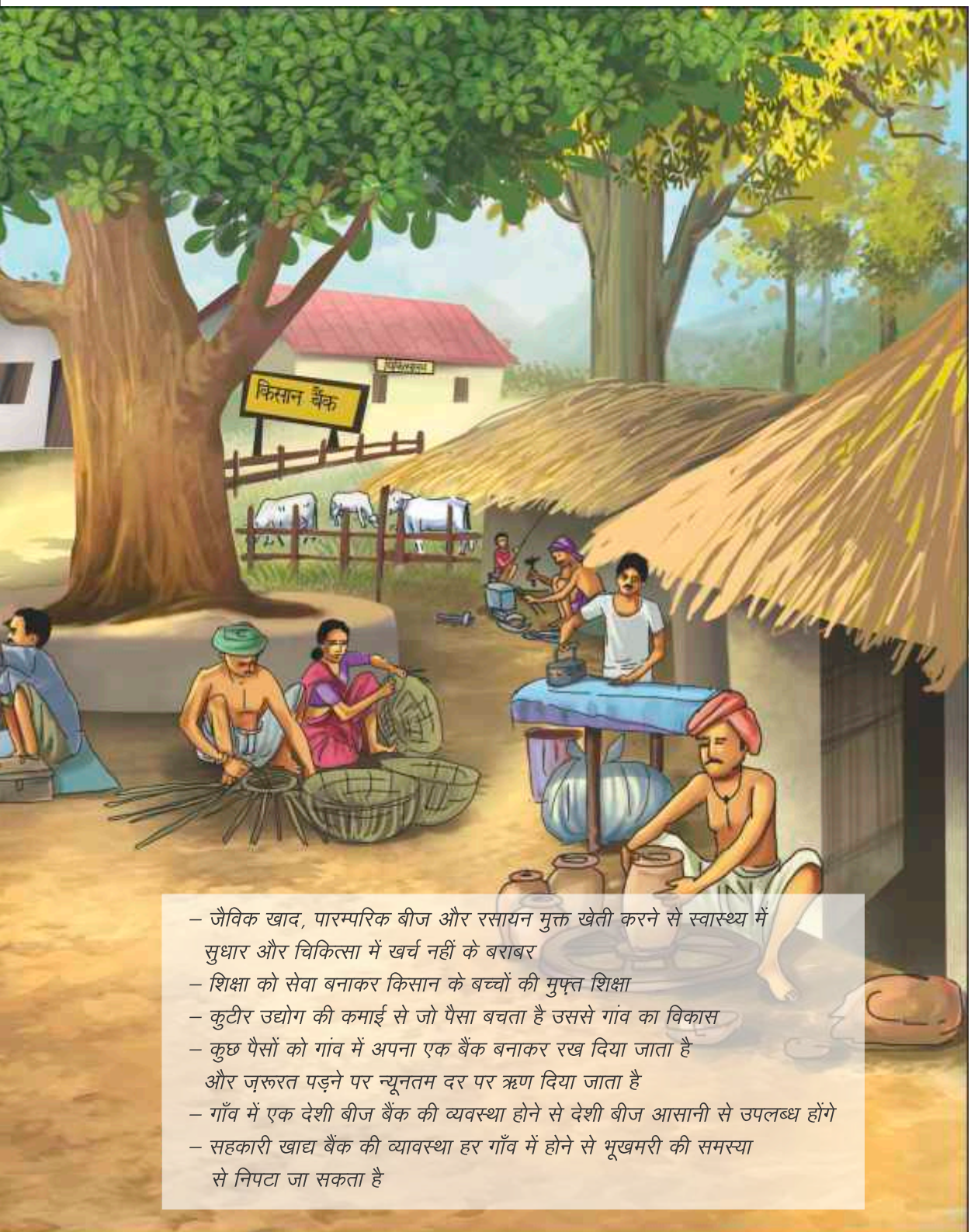

– जैविक खाद, पारम्परिक बीज और रसायन मुक्त खेती करने से स्वास्थ्य में सुधार और चिकित्सा में खर्च नहीं के बराबर
– शिक्षा को सेवा बनाकर किसान के बच्चों की मुफ्त शिक्षा
– कुटीर उद्योग की कमाई से जो पैसा बचता है उससे गांव का विकास
– कुछ पैसों को गांव में अपना एक बैंक बनाकर रख दिया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर न्यूनतम दर पर ऋण दिया जाता है
– गाँव में एक देशी बीज बैंक की व्यवस्था होने से देशी बीज आसानी से उपलब्ध होंगे
– सहकारी खाद्य बैंक की व्यावस्था हर गाँव में होने से भूखमरी की समस्या से निपटा जा सकता है

फोकस ऑन द ग्लोबल साउथ

फोकस ऑन द ग्लोबल साउथ, एशिया (थाईलैंड, फिलीपीन्स एवं भारत) में स्थित एक नीति शोध संगठन है। फोकस भारत एवं विश्व के दक्षिण भाग (यानी विकासशील देशों) में वैश्वीकरण की राजनीतिक अर्थव्यवस्था और इस प्रक्रिया में अंतर्निहित प्रमुख संस्थाओं के बारे में शोध तथा विश्लेषण प्रदान कर सामाजिक आंदोलनों एवं समुदायों की सहायता करता है। फोकस के लक्ष्य दमनकारी आर्थिक एवं राजनीतिक संरचनाओं की समाप्ति, स्वतंत्र संरचनाओं तथा संस्थाओं का निर्माण, विसैन्यीकरण और शांति को बढ़ावा देना है।

रोज़ा लक्जमबर्ग स्टिफतुंग (आर.एल.एस.)

रोज़ा लक्जमबर्ग स्टिफटुंग (आर.एल.एस.) जर्मनी में स्थित एक फाउंडेशन है, जो दक्षिण एशिया की तरह ही विश्व के अन्य भागों में महत्वपूर्ण सामाजिक विश्लेषण और नागरिक शिक्षा के विषयों पर कार्य कर रहा है। यह एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य समाज एवं नीति निर्धारकों के सामने वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है। यह शोध संगठनों, स्व–मुक्ति के लिए संघर्ष करने वाले समूहों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को उन मॉडल्स के विकास में उनकी पहलों में मदद देता है, जिनमें अत्यधिक सामाजिक एवं आर्थिक न्याय देने की क्षमता है।